श्रीमती सुषमा स्वराज: यह ठीक नहीं है। हम सदन से वाकआउट करते हैं। ...(**व्यवधान**)...

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: आप अगर अनुमति नहीं देंगे तो यह ठीक नहीं है। ...(**व्यवधान**)... आप उन्हें संरक्षण दे रहे हैं, यह बिल्कुल ठीक नहीं है। ...(**व्यवधान**)... हम इससे पूरी तरह से असहमत हैं और सदन से वाकआउट करते हैं। ...(**व्यवधान**)...

(तत्पश्चात कुछ माननीय सदस्य सदन से उठकर चले गए)

DR. V. MAITREYAN: The House is discussing questions. It is not discussing the most important question which the country is asking, and it was asked to a person no less than the Prime Minister. ...(*Interruptions*)... In protest, we are walking out.

(At this stage some hon. Members left the Chamber.) ...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: Please let the Supplementary questions be asked.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

महिला सशक्तिकरण

*481. **श्री जनेश्वर मिश्र: क्या महिला और बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि लन्दन स्कूल ऑफ ओरिएण्टल एण्ड अफ्रीकन स्टडीज द्वारा हाल ही में तैयार की गई एक रिपोर्ट में महिलाओं के प्रति उपेक्षा और उनकी दयनीय अवस्था की ओर इंशारा किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या तथाकथित महिला सशक्तिकरण देश की आधी आबादी के साथ धोखा साबित हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार महिलाओं को इन मूलभूत समस्याओं से निज़ात दिलाने में समर्थ बनाने के लिए कोई कारगर योजना बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी): (क) से (घ) विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) सरकार को लंदन स्कूल ऑफ ओरियण्टल एण्ड अफ्रीकन स्टडीज़ की इस प्रकार की किसी रिपोर्ट की जानकारी नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

Women empowerment

†*481. SHRI JANESHWAR MISHRA: Will the Minister of WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a report prepared recently by London School of Oriental & African Studies, has indicated about the negligence towards and poor condition of women;

(b) if so, whether the so called women empowerment is proving to be deceptive, with half of the population of the country;

†Original notice of the question was received in Hindi.

(c) if so, whether Government is formulating any effective scheme to enable women to get rid of these basic problems; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT (SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Government is not aware of any such report of the London School of Oriental & African Studies.

(b) to (d) Do not arise.

श्री जनेश्वर मिश्र: मान्यवर, जो जवाब रेणुका जी के नाम से आया है, मैं उनको बहुत तेजस्वी महिला मानता हूं। बहुत दिनों तक हम लोगों ने साथ-साथ काम किया है। लेकिन यह इतना निराशाजनक है कि मैं हतप्रभ हूं कि ऐसा जवाब कैसे आ गया। मान्यवर, महिलाओं के बारे में यह सवाल है, विशेष तौर से उनकी दुर्दशा के बारे में और दुनिया भर में इस पर जो रिपोर्ट आई है उसको लेकर के। एक रिपोर्ट आई थी जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ ने जारी किया था। उसकी महिला मेंबर थी, जिसने अपनी रिपोर्ट दी थी। हिन्दुस्तान के अखबारों में यह छप चुका है। सरकार की तरफ से जवाब आया कि हमें इस तरह की रिपोर्ट की कोई जानकारी नहीं है। फिर हमने पूछा कि उनके सुधार के लिए कोई तरीका अख्त्यार किया जाएगा? जवाब आया कि question does not arise. फिर हमने कहा कि क्या भविष्य में कुछ सुधार होगा? जिस पर फिर जवाब था कि question does not arise. ये जवाब आप पढ़ लीजिए। इससे हम हतप्रभ हो गए, शायद दुनिया में महिलाओं का सम्मान पुरुषों के मुकाबले कम है। लेकिन हिन्दुस्तान दुनिया के और देशों के मुकाबले एक प्रगतिशील देश है। फिर भी हमारे यहां महिला को राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री होने का गौरव मिला है। बहुत से देश यह मौका नहीं देते। लेकिन यहां की महिला जिस तरह से सताई जाती है, उसकी जानकारी तो सरकार को होनी चाहिए। इन्होंने महिला साक्षरता के लिए एक योजना बनाई है और बगल में गुड़गांव के पास एक मेवात है, उसी योजना के तहत महिलाओं के स्कूल के लिए 7 मैट्रिक पास व्यस्क महिलाएं चाहिए। पूरे मेवात में 62 गांव में 7 महिलाएं मैट्रिक पास नहीं हैं।

श्री सभापति: आप प्रश्न पूछ लें।

श्री जनेश्वर मिश्र: जो कोई आप अभियान चला रहे हैं, उस अभियान के लिए 62 गांवों में केवल 7 मैट्रिक महिलाएं नहीं हैं, तो स्कूल कैसे चलेगा। आप कह देंगे मंत्रालय की तरफ से हमें जानकारी नहीं है कि मेवात जिले में क्या हो रहा है। यह जानकर हम लोग सदन में क्या करेंगे। इसलिए मैं साफ-साफ जानना चाहूंगा?

श्री वी॰ नारायणसामी: सवाल पूछिए।

श्री जनेश्वर मिश्र: सवाल तो बहुत व्यापक है। इसलिए मैं साफ-साफ जानना चाहूंगा कि कम से कम सरकार की तरफ से महिलाओं के उत्थान के लिए जितने कार्यक्रम हुए हैं, क्या कभी देखा गया है कि उनका कार्यान्वयन हो रहा है और अगर देखा गया है तो उस पर क्या रिपोर्ट है, यह हम जवाब में चाहेंगे?

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Mr. Chairman, Sir, I want to thank the hon. Member for giving me this compliment in the beginning. But I also want to point out that the question is very, very specific and it refers to a report prepared by the London School of Oriental and African Studies, which has indicated about the negligence towards poor conditions of women. The reply that we have drafted directly addresses that very issue that we are not aware of this particular study. We have on record an e-mail, which I can forward to the hon. Member later, in which the school has said that they are not aware of what these

studies are and from where these reports have been culled and derived. Hence my inability and my limitations. I cannot misguide the House by quoting from a report about which I do not know anything. Sir, Shri Janeshwar Mishra is a senior and seasoned politician for whom we have great respect. We are aware of the outstanding works that he has done in various activities. There is no doubt about the commitment of this Government or my personal commitment towards the issue of women and child development. We have a more holistic approach where we dovetail and take interventions, along with other Ministries, to ensure that there is enabling and empowered atomosphere in the country for women. We do vote for political, social and economic development as well as gender justice, gender budgeting and advocacy which is done at various levels. There are exhaustive schemes which speak about this. There are exhaustive schemes which speak about this. And we are approaching the Eleventh Plan in a pro-active way so that we plug, if there are any in the first-place, the loopholes, to ensure that the safety net that we give to woman and child development and empowerment will continue to rise dramatically, and the infant mortality, maternal mortality, feeding of child, nutrition, access to food security, education, immunisation, domestic violence, all these, are taken care of. Now, despite the fact that it is State Governments, which are supposed to be having the authority to ensure implementation of this, I don't think I am known to be polite or patient and wait for States to deliver. We have been pro-active in various States to ensure that studies and comparatives, as well as, interventions are taken to protect these women. For example, the Domestic Violence Act, which we brought in last year,...

MR. CHAIRMAN: Let him put his second supplementary.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: He has put a specific supplementary, and hence I am answering it. I would like to mention that this Act was reviewed within a period of one year; perhaps, the first time ever that the Government of India had taken this on a pro-active manner, and we have shown dramatic results in that.

श्री जनेश्वर मिश्र: सर, हमको भी इतना ही लम्बा सवाल पूछने की इजाजत दे दीजिए, जितना लम्बा जबाव मंत्री महोदया दे रही हैं। मैं बहुत ही अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि इतने लम्बे जबाव के लिए मैंने यह प्रश्न नहीं पूछा था। मैं ने एक खास बात पूछी थी। मैं पहले वाले सवाल की बात कर रहा हूं, मैं सेंकड सप्लीमेंट्री के बारे में नहीं कह रहा हूं।

श्री सभापति: अब आप दूसरा सवाल पूछ लीजिए। पहले का तो उन्होंने जबाव दे दिया कि वह रिपोर्ट नहीं है।

श्री जनेश्वर मिश्र: सर, नहीं दिया। बगल के मेवात में, जहां लड़कियों के लिए पढ़ने के स्कूल हैं, सात अध्यापिकाएं एक स्कूल में होती हैं और 62 गांव में मैट्रिक पास सात अध्यापिकाओं के लायक कोई महिला नहीं है, यह मेरा सवाल था। इस सवाल को वह घुमा रही थीं कि मैक्सिमम पॉसेबिल तरक्की दिला रही हैं, ये सरकार की बोली सुना रही थीं और लम्बा सुना रही थीं।

सर, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि यह कानून बनाने से आदमी की जो मान्यताएं हैं, वे नहीं बदला करती हैं। महिला हर घर में अपमानित है। एक तरफ इस देश में कहा गया है कि जहां नारी की पूजा होती है, वहां देवता बसते हैं और दूसरी तरफ शूद्र, गंवार, ढोर, पशु, नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, यह भी कहा गया है। यह किसी भी महाकाव्य में लिखा हो, लेकिन इस वाक्य को जब कोई महिला पढ़ती होगी, देश की नहीं दुनिया की, तो उसके ऊपर क्या गुजरती होगी, इसकी कल्पना कीजिएगा। क्या सरकार में यह हिम्मत है कि उस महाकाव्य से इस वाक्य को निकाल दे या इसको एक्सपंज करने का फैसला कर ले, नहीं कर सकती है। महिला को ढांढस बंधाने के लिए, ताकत दिखाने के लिए पैसा नहीं चाहिए, उसके दिल को ताकत चाहिए और वह नहीं मिल रही है, इसलिए मैं....।

श्री सभापति: जनेश्वर जी, आप सवाल पूछ लीजिए, ताकि दूसरे सप्लीमेंट्रीज भी हो सकें।

श्री जनेश्वर मिश्र: सर, मैं आ रहा हूं, क्योंकि कई बार जब हमारी महिला मित्र तैंतीस प्रतिशत आरक्षण के लिए कहती हैं, तो हमको लगता है कि यह बनावटी सवाल है, यह तो बहुत दुर्दशा है। यहां सदन में बहुत से लोग बिहार, मध्य प्रदेश के बैठे होंगे, उनकी महिलाओं को दूध पीने की इजाजत नहीं है। उनके चूल्हे में दो तरह का चावल पकता है, मर्द के लिए अलग, औरत या लड़की के लिए अलग। सदर साहब, अगर यह तस्वीर हमारे दिमाग में नहीं रहेगी, तो सरकार इस तरह से जबाव देती रहेगी, हम इसका हल ढूंढ़ते रहेंगे। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि जो हर घर में महिलाओं के लिए भेदभाव बरतने वाला तौर-तरीका है, उनके लिए कानून नहीं है, यह तौर-तरीका कितना भयानक है, इसको आप जानते हैं। इस रिपोर्ट में लिखा है...।

श्री सभापति: आप सवाल पूछ लीजिए।

श्री जनेश्वर मिश्र: सर, मैं सवाल पर ही आ रहा हूं। इस रिपोर्ट में लिखा है कि अगर उस महिला के साथ उसका पति भी दुर्व्यवहार करे, तो उसके बारे में अपनी कानून की किताब में नहीं लिखा है। इसको पढ़ने के बाद मैंने अपनी कानून की किताब को देखा, उसमें भी पति अगर अपनी पत्नी से बलात्कार करे, तो उस पर भी वही ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: जनेवश्वर जी, आप सवाल पूछ लीजए। आप जो बात कह रहे हैं, वह अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। मगर सवाल से रिलेटिड नहीं है।

श्री जनेश्वर मिश्र: सर, जिन मुद्दों की तरफ मैंने अभी इशारा किया, क्या सरकार उन कानूनों को, जिनमें कि महिला का अतिशोषण हो रहा है, खानपान से लेकर के और घर के भीतर तक, उसका कोई निदान निकल सके?

श्रीमती रेणुका चौधरी: सभापति जी, मैं मानती हूं कि हमारे देश में मानसिक तौर पर हम मंदिर जाकर देवी माता के आगे माथा टेकते हैं और घर आकर उनके गले घोंट देते हैं। मैं मानती हूं कि इस देश में हम आज भी भ्रूण हत्या करते हैं और लड़कियों, अजन्मी बच्चियों का शिकार करते हैं। हमने कानूनी तौर पर कई कदम उठाए हैं। आज के दिन यदि आप देश भर में एक नजर डालेंगे तो आपको दिखेगा कि पंचायती राज में कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसको राजीव गांधी जी अमल में लाए थे, उसकी वजह से आज के दिन देश में Not just one million, but ten million women are empowered because of capacity building, because they have participated in this process of capacity building by contesting elections. उसके अलावा भी हमने कई कदम उठाए हैं। इसमें आप देखेंगे कि यह औरत को सिर्फ शिक्षित ही नहीं, बल्कि सुरक्षित और सशक्त करने से संबंधित है। There is no doubt about our commitment. सर, लेंथी आन्सर का सवाल नहीं है। आपने सवाल पूछा था पति हाथ उठाएगा तो इसके लिए कानून बनने चाहिए, बेशक बनने चाहिए, हमने ये कानून बना दिए हैं। "गृह हिंसा कानून" हमने 2007 में लागू किया है। इसके विरोध में कई पत्नी पीड़ित सेवा वालों ने आवाज उठाई है। मैं सोचती हूं कि It is very important law और हमने इसे एक साल के अंदर रिव्यू भी किया है। आश्चर्य की बात है कि इन इलाकों में, जहां हम सोचते हैं कि महिला बहुत ट्रेडिशनल है, वहां से भी हमें शिकायतें मिली हैं। कई राज्यों में तीन हजार से ज्यादा शिकायतें मिली हैं। हम इसे रिव्यू करके, हर स्टेट में लागू करके ऑफीसर्स की अपोइन्टमेंट के लिए जोर दे रहे हैं। मैं चाहती हूं कि हाउस के सभी मैम्बर्स हमारा साथ दें। अपने-अपने इलाकों में देखें कि जो कानून हमने बनाएं हैं, उनको अमल में लाने में हमें सहायता दें। हमें आपकी बहुत बड़ी सहायता चाहिए। ...(व्यवधान)...

श्री जनेश्वर मिश्र: दो तरह के चावल ...(व्यवधान)...

श्रीमती रेणुका चौधरी: दो तरह के चावल स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। हम यहां से चावल पकाकर नहीं भिजवाते हैं, हम सिर्फ पैसा देते हैं। अगर आपकी जानकारी में कुछ है तो मैं अवश्य जाकर देखूंगी और मैं चाहती हूं दो तरह के चावल हों। औरतों के चावल पौष्टिक हों और फोर्टिफाइड हों, विटामिन ऐडेड हों जो इन्फैंट मोर्टेलिटी और मेटरनल मोर्टेलिटी के लिए उपयुक्त हों।

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Sir, we are taking advantage of the question relating to women asked by the hon. Member, although there are many, many reports within the country, not necessarily only of the London School of Oriental Studies, about the status of women. My specific question to the hon. Minister, Sir, is this.

I know it was the intention at the time of the appointment of the National Commission for Women that every year the Annual Report of the National Commission for Women will be tabled in both the Houses and that it will be discussed in Parliament. I do not think that is happening. I would like to ask if the hon. Minister will take steps now to ensure that the Annual Report of the National Commission for Women is tabled in Parliament and it is discussed every year just like the Demands-for Grants are.

Secondly, Sir, according to the judgment of the Supreme Court, in the case of sexual harassment against women in the workplace, there are meant to be peer committees appointed in every Government department, both at the Centre as also in the States; at least, in all the Government departments at the Centre. Have these been set up and are they functioning?

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: How wonderful, Jayanthiji! I must congratulate you for raising this issue because not often these issues are raised and not enough people think that it is important to do that. But I have also to confess that, having said all that, we depend heavily on other Ministries to be able to give us the ATRs of their Ministries so that we can compile them and table them in Parliament. But I would welcome Members to raise this issue and take it up for discussion and I would be very happy to reply to that. Also, through you, Sir, I would like to tell the House, that we are using our offices and breathing down the necks of the various Ministries so that they give us their ATRs.

SHRIMATI BRINDA KARAT: Sir, my question relates to one of the very important components of the women's empowerment policy that the Government has adopted and that concerns the functioning of the National Commission for Women. Sir, my question to the hon. Minister is that, at present, the status of the National Commission for Women, which is supposed to be the focal agency outside the Government to look after the interests of the women is much lower than the status of all the other Commissions, whether it is the National Minorities Commission, whether it is the Human Rights Commission, whether it is the SC & ST Commission, whether it is the National Child Rights Commission. Every single Commission has a status which is higher than that of the National Commission for Women. Now, my question is, since the nodal agency is being disempowered, what is the Minister doing to ensure that the Chairperson of the Commission has the same status? Has the Minister been to the Prime Minister on this, raised the issue in the Cabinet? I am asking this because not only is the status being devalued, but at the same time, there is no Chairperson to the National Commission for Women, So, this is the situation of the nodal...*(Interruptions)*...There is no Chairperson...

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Who said?

SHRIMATI BRINDA KARAT: The Chairperson's term is over.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: No, no; Dr. Girija Vyas is there.

SHRIMATI BRINDA KARAT: Excuse me. The Chairperson's term is over in February.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Okay; let me answer that.

SHRIMATI BRINDA KARAT: Please, you can correct me. The Chairperson's term is over in February, there is no Chair. A large number of members' terms are also going to be over in May. Is the hon. Minister aware of that or not? But, my point is that the Commission is completely disempowered. What is the Minister doing about it, since it comes under your Ministry?

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Sir, I want to set a few things right on record. First of all, there is no question of not having a Chairperson in place. Dr. Girija Vyas ...*(Interruptions)*...

SHRI PENUMALLI MADHU: Sir, every day we are facing power problem in Delhi. ...*(Interruptions)*... It is a big problem. See, how it is affecting the functioning of the House. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Please, let the question be answered. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI BRINDA KARAT: Sir, this is representative of women being powerless. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Let the question be answered. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI BRINDA KARAT: This is representative of women's powerlessness. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Please, let the question be answered. ...*(Interruptions)*...

SHRI PENUMALLI MADHU: There is no power in Parliament. What is this? ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI BRINDA KARAT: Sir, it is symbolic of women's powerlessness. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: I don't think women are dependent on electricity to be powerful. ...*(Interruptions)*... I think we have far more power, and we can light up a lot more than the Electricity Department. ...*(Interruptions)*... But, I am ready to ...*(Interruptions)*... I think the women are so powerful that we can dispel the darkness and gloom across the country. ...*(Interruptions)*... We don't need that electricity and *bijali-batti,* which may be the main need, we are quite capable of doing it on our own...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Let the question be answered, please.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Sir, the point is, first of all, I would like to inform the hon. Member that there is a Chairperson in the National Commission for Women. Dr. Girija Vyas has been re-nominated as the Chairperson of the National Commission for Women. She is very much in the Chair, and she continues to do her work as effectively as she has always done. The NCW has taken up all the cases *suo motu*, and they are addressing that. The hon. Member is right in saying that four other members are retiring. Don't worry, before they retire, the decision will be taken about who is going to be in the Commission. The Commission will function effectively, as always. Now, the amendment of the NCW Act is under consideration. We are taking it up. The procedures to be complied with, before I approach the Cabinet, for which we are actively involved in.

MR. CHAIRMAN: Now, Shrimati Viplove Thakur.

SHRIMATI BRINDA KARAT: You have not replied about increasing the status of the NCW.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Yes, it is a statutory body.

SHRIMATI BRINDA KARAT: Renukaji, I am asking about the status of the Commission.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: I said that we are looking into the issues before

we go to the Cabinet. Please, leave it to me. I think, I am the one who is in-charge of it. We will do it.

SHRIMATI BRINDA KARAT: No, no; we cannot leave it to you. How can we leave it to...

MR. CHAIRMAN: Let the decision be taken on it. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI BRINDA KARAT: Sir, we cannot leave it to the Minister. ...*(Interruptions)*... It is four years. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: I am afraid, that is...*(Interruptions)*... Yes, please.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: How can I give an assurance to the House, before I complete the work? ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Shrimati Viplove Thakur, please.

श्रीमती विप्लव ठाकुर: माननीय सभापति जी, जो हमारे बहुत seasoned politician हैं, उन्होंने women and child के बारे में बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि हम महिला-महिला करते हैं, क्या वे पुरुषों के लिए भी कोई ऐसा कैंप लगाने जा रही हैं, Awareness Camp ...(**व्यवधान**)... सुनिए, जिसमें उनके mind-set को, जो सदियों से बना हुआ है, उसको बदलने के लिए कोई ऐसा कदम उठाने जा रही हैं, क्या उसको भी इसमें लाने जा रही हैं? जब तक हम पुरुषों के mindset को नहीं बदलेंगे, तब तक हम महिलाओं के बारे में जितनी बात करते जाएं हम यहां जरूर बोल कर जाते हैं, लेकिन घर में वही हालत होती है, मुहल्ले में वही हालत होती है। मैं यह जानना चाहती हूं।

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Sir, let me tell you, it is a very pertinent question because, I think, men cannot afford to remain the problem. They have to become part of the solution to address this. It is true that if the woman is not associated with the man, she does not have many problems. No *sati* without *pati*. ...*(Interruptions)*... You see, everywhere, it is a comparative. We have now set up an initiative where we are calling for a round table conference where a lot of men's representatives, including those from *Patni Peedit Seva* and such associations. The victims of 498A, as they call themselves, are coming to meet us on this round table and we have social behavioural psychologists and other people involved in this to understand what provokes a man to beat his wife, what instigates domestic violence, how does the man see his life partner as less than the dowry that she brings and does not view her as a recurring deposit, what motivates the man...*(Interruptions)*...

श्री अमर सिंह: क्या मंत्री महोदया सती प्रथा के पक्ष में हैं? अभी उन्होंने सती का उद्धरण दिया है। Do you favour *sati?*

श्रीमती विप्लव ठाकुर: नहीं, नहीं, उन्होंने यह नहीं कहा। उन्होंने तो कहा है कि पति न हो तो सती भी नहीं होगी... (**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: We will go to the next Question, 482...*(Interruptions)*...

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: I have said no *sati* without *pati*.

अगर वह पति से जुड़े तभी तो सती की बात आती है, नहीं तो इसका सवाल ही नहीं उठता है।

Enlistment of OBCs

*482. SHRI ABU ASIM AZMI: Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to state:

(a) whether there is a proposal under active consideration of the Central Government to enlist Other Backward Classes (OBCs), besides Scheduled Castes/Scheduled Tribes;